कंचन और अन्य

बनाम

राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य

17 जनवरी 2006

[अरिजीत पसायत और तरूण चटर्जी, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988; धारा 68(3)(बी):

ट्रांसपोर्टरों को परमिट देना-पुरानी परिवहन प्राधिकरण/एसटीए की शक्ति-गलत इरादे से आयोजित: प्राधिकारियों ने ऐसे परमिट देने के लिए आवेदन दाखिल किए बिना भी ट्रांसपोर्टरों को परमिट दे दिए-मेलर में सतर्कता पूछताछ के बहाने अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए-... दुर्भावना के प्रश्न पर निर्णय लेने में यदि प्राधिकारियों ने बिना सोचे-समझे कार्य किया है, तो प्राधिकारी का कौन सा कार्य दुर्भावना के प्रश्न पर उसके विरुद्ध कार्रवाई में भेद्यता जोड़ने के लिए पर्याप्त है-

इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने परमिट देने में अधिकारियों की दुर्भावना को सही पाया।

इन अपीलों में जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ताओं/ट्रांसपोर्टरों को दिया गया परमिट कानूनी रूप से बरकरार रखा जा सकता है। इस प्रकार दिए गए परमिट को राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि अधिकारियों की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी। अपील पर, ट्रिब्यूनल के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया, "इस तथ्य पर ध्यान दें कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के रूप में चलने योग्य नहीं थी, मौजूदा ऑपरेटरों के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था। अधिकारियों ने, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68(3)(बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट देने की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी और अपनी शक्ति का वास्तविक प्रयोग करते हुए परमिट जारी कर दिए थे; और उच्च न्यायालय ने जिन कमजोरियों को उजागर किया है, उनके बारे में ट्रिब्यूनल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में कोई विशेष चुनौती नहीं थी।

उत्तरदाताओं ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से गैर-पारदर्शिता और दुर्भावना की बू आ रही है; 48 परमिट दिए गए और

कुछ मामलों में, ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश की गई फाइलों से संकेत मिलता है कि परमिट देने के लिए आवेदन भी नहीं थे; परमिट उसी दिन दिए गए थे जिस दिन राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटी ए) ने कथित तौर पर अधिनियम की धारा 68(3) (बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमिट देने की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी, और वह भी इसके संबंध में कोई अधिसूचना जारी किए बिना इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि एसटीए कानून के विपरीत काम कर रहा था; और यह कि अधिनियम की धारा 68(3)(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्ता संभालने से बहुत पहले एसटी ए के लिए आवेदन कैसे किए जा सकते थे।

अपीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।

1.1. यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है. राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की दुर्भावना के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष ट्रिब्यूनल द्वारा देखे गए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि ऐसे मामले में परमिट देने के लिए आवेदन भी नहीं थे। यह बात हैरान करने वाली है कि बिना आवेदन के भी परमिट कैसे दिया जा सकता है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परमिट देने से संबंधित सभी 48 फाइलें पेश नहीं कीं। दलील दी गई कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

कर रहे सतर्कता अधिकारियों ने कुछ फाइलें अपने कब्जे में ले लीं। जो भी हो, तथ्य यह है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत किए गए कुछ मामलों में आवेदन नहीं थे। [454-डी-ई]

1.2. दुर्भावना के प्रश्न का निर्णय करते समय, यह तथ्य कि कुछ मामलों में, अधिकारियों ने बिना सोचे समझे कार्य किया है, अपने आप में कार्रवाई में भेद्यता जोड़ने के लिए पर्याप्त है। [454-एफ]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने अध्यक्ष बनाम ओमादित्य वर्मा एवं अन्य के माध्यम से .. **[2005] 4 एससीसी 424, संदर्भित)**।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7305/2003। (सिविल विविध रिट याचिका संख्या 48624/2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.4.2003 से।)

साथ

C.A.No.7306/2003 और Cont.Pet.(C) No.159/2005 C.A.No.7306/2003

अपीलकर्ताओं की ओर से विजय हंसारिया, पी.डी. शर्मा और मिनाक्षी शर्मा।

उत्तरदाताओं के लिए राकेश द्विवेदी, रणजीत कुमार, सुश्री गौरी छाबड़ा, सुश्री सुधा पाल, श्रीमती रानी छाबड़ा, प्रमोद स्वरूप, प्रमोद दयाल और प्रदीप मिश्रा।

हस्तक्षेपकर्ता के लिए दिनेश द्विवेदी एवं प्रशांत चौधरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.

इन अपीलों में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के समग्र आदेश को दी गई है। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण, यू.पी.लखनऊ (संक्षेप में 'एस.टी.ए.') द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई धनराशि को कानूनी रूप से बरकरार रखा जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गैर-आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक पुनरीक्षण पर, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, यू.पी., लखनऊ (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') ने पेनिट्स के अनुदान को रद्द कर दिया और माना कि एसटीए की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी; इसने वैधानिक आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन किया था और इसलिए, परमिट देना

एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं थी। ट्रिब्यूनल का यह आदेश रिट याचिकाओं में चुनौती का विषय था। उच्च न्यायालय अनिवार्य रूप से तीन निष्कर्षों को दर्ज करने आया था; (ए) अधिसूचित मार्गों के संबंध में, परमिट नहीं दिए जा सकते थे; (बी) मार्ग को अपने कब्जे में लेने में एसटीए की कार्रवाई अनुचित, गैर-कानूनी थी और (सी) परमिट देने में एसटीए द्वारा शक्ति का प्रयोग गैर-मान्यतापूर्ण होने के कारण समान रूप से अस्थिर था।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की गई पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि जिन मौजूदा ऑपरेटरों ने पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, उनके पास इसे दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय एक गलत धारणा पर आगे बढ़ा जैसे कि मार्ग अधिसूचित मार्ग थे। एसटीए ने, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 68(3)(बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट देने की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी और वास्तव में इसका वास्तविक अभ्यास करते हुए, परमिट जारी करने का निर्देश दिया। यह बताया गया कि तथाकथित अनंतताओं के बारे में ट्रिब्यूनल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में कोई विशेष चुनौती नहीं थी,

जिसे उच्च न्यायालय ने उजागर किया है। संक्षेप में, प्रस्तुत किया गया था कि ट्रिब्यूनल द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग अड़ियल था और ट्रिब्यूनल द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई उचित आधार नहीं था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी।

जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से गैर-पारदर्शिता और दुर्भावना की बू आती है। यह बताया गया कि 48 परमिट दिए गए थे और कुछ मामलों में, ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश की गई फाइलों से संकेत मिलता है कि परमिट देने के लिए आवेदन भी नहीं थे। इसके अलावा, तथ्य यह है कि परमिट उसी आधार पर दिए गए थे जिस पर एसटीए ने कथित तौर पर धारा 68(3)(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमिट देने की शक्ति अपने हाथ में ले ली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसटीए कानून के विपरीत कार्य कर रहा है। यह बताया गया है कि यह मान भी लिया जाए कि कोई समाधान था, जो कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अनुसार भी एक तथ्य नहीं है, एसटीए द्वारा अधिकार क्षेत्र को संभालने के बारे में कोई अधिसूचना नहीं थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अधिनियम की धारा 68(3)(बी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सत्ता संभालने से बहुत पहले एसटीए को आवेदन कैसे किए जा सकते थे। अंत में, आवेदन आरटीए

को किए जाने हैं और किसी को नहीं पता कि एसटीए को आवेदन किन परिस्थितियों में किए गए थे।

हम इसे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानते हैं। एसटीए की विधायकी के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष ट्रिब्यूनल द्वारा देखे गए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि ऐसे मामलों में पेनिट्स देने के लिए आवेदन भी नहीं किए गए थे। यह बात हैरान करने वाली है कि बिना आवेदन के भी परमिट कैसे दिया जा सकता है। एसटीए ने, सबसे अच्छे से ज्ञात कारणों से, परमिट देने से संबंधित सभी 48 फाइलें प्रस्तुत नहीं कीं। दलील दी गई कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारियों ने कुछ फाइलें अपने कब्जे में ले लीं। जो भी हो, तथ्य यह है कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत किए गए कुछ मामलों में आवेदन नहीं थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का यह रुख कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को राहत देने से इनकार किया जा सकता है, स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। दुर्भावना के प्रश्न का निर्णय करते समय। यह तथ्य कि कुछ मामलों में, अधिकारियों ने बिना दिमाग लगाए काम किया है, अपने आप में कार्रवाई में भेद्यता जोड़ने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हम अन्य प्रश्नों पर जाना जरूरी नहीं

समझते और अपीलें खारिज की जाती हैं। परिणामस्वरूप पारित सभी अंतरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। शुरू की गई अवमानना कार्यवाही रद्द कर दी जाएगी।

हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन यह कहते हुए दायर किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष बनाम उमादित्य वर्मा और अन्य, (2005] 4 एससीसी 424 के माध्यम से की गई कुछ टिप्पणियाँ सही नहीं हैं। हम इस एप्लिकेशन में उस प्रश्न से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसलिए हस्तक्षेप के लिए आवेदन खारिज किया जाता है।

एच एस.के.एस.

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।